अवस्था से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में झाड़न के रूप में कितने प्रतिशत सीमेंट बर्बाद हो जाता है और प्रति वर्ष बर्बाद होने वाले सीमेंट का मूल्य कितना है ,

(ख) उक्त बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं और सरकार कहां तक सफल रही है ;और

(ग) क्या यह सच है कि रूंचिका जूटेक्स, जयपुर ने सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवर्ष होने वाले लगभग 300 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय क्षति को रोकने के लिए उपायों का सुझाव दिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1985-86 में सीमेंट का उत्पादन 331 लाख मी. टन था । नेशनल कौंसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स तथा पटसन आयुक्त द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार रिसाव के कारण अनुमानत: 1 से 1.2 प्रतिशत तक सीमेंट बर्बाद हो जाता है । मूल्य के अनुसार यह हानि 40 करोड़ रुपये से 45 करोड़ रुपये तक की हो सकती है ।

(ख) रखने-उठाने आदि के दौरान जो सीमेंट की बर्बादी होती है उसे न्यूनतम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्य किये हैं जिनसे काफी सफलता मिली है :—

(1) पुराने गनी बैगों (बोरियों) के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना ।

(2) 1.10.82 से सुधरी हुई बनाई वाले तथा भारतीय मानक संस्थान (आई.एस.आई.) क्वालिटी के शत-प्रतिशत नयी जूट बोरियों का उपयोग अनिवार्य करना ।

(3) ड्रमों/कन्टेनरों में सीमेंट की बल्क मात्रा भेजने हेतु प्रोत्साहन देना ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक विकास विभाग को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Posts of Judges in Madras High Court

44. SHRI R. MOHANARANGAM: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether the entire vacancies of Judges in Madras High Court have been filled up; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Out of the sanctioned strength of 25 permanent Judges, there are at present 5 vacancies of Judges in Madras High Court. Appointment of one person as a Judge has been approved and is to be notified shortly. Matter of filling up the remaining vacancies is engaging the attention of the Government in consultation with the authorities prescribed in the Constitution.

Contract for HBJ Pipeline

45. SHRIMATI KRISHNA KAUL:
SHRI K. VASUDEVA PANICKER:
SHRI SHANKER SINH VAGHELA:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) Whether Government have since awarded the contract for H.B.J. Pipeline;

(b) if so, the details of the name of the firm and terms thereof;

(c) if not, the reasons for the delay:

(d) by when the contract is likely to be awarded; and

(e) the time by which the construction of the pipeline is likely to be completed?